

35

## INSTITUTIONAL FINANCE & CREDIT CONTROL DEPARTMENT, HARYANA

### (Note on Activities and Achievements)

#### 1. **INTRODUCTORY**

Haryana Govt. is giving a lot of importance to institutional finance as the institutional finance available through Commercial Banks, Cooperative Banks and other term lending institutions as it reduces pressure on the budgetary resources of the State Govt. In Haryana, the role of the Government has been to persuade the banking institutions to give importance to the Agricultural & Allied Sectors, particularly to the poverty alleviation programmes.

#### 2. **OVERALL EXPANSION OF BANKING ACTIVITIES IN HARYANA**

At the time of nationalisation of banks, in the year 1969, there were only 174 bank branches in Haryana with total deposits of Rs. 64.10 crores and total advances of Rs. 30.27 crores, with a credit-deposit ratio of 47%. At the end of March 2009, the number of bank branches has increased to 2112 with total deposits of Rs. 82875 crores and total advances of Rs. 64738 crores giving a total credit-deposit ratio of 78% per cent.

#### 3. **REVIEW OF ANNUAL CREDIT PLAN 2008-09**

The Annual Credit Plan for the year 2008-09 aimed at providing credit to the tune of Rs.24608.38 crores in Haryana State out of which Rs. 17229.67 crores (70%) was for Agriculture and Allied Sector, Rs. 3443.59 crores (14%) for MSE Sector and Rs. 3935.12 crores (16%) for Tertiary Sector respectively.

During the financial year 2008-09, the total amount advanced has been to the tune of Rs. 23015.80 crores (93.5% of the target) by the end of March, 2009 under the Annual Credit Plan 2008-09. Out of this total lending of Rs. 23015.80 crores, Rs.14201.21 crores have gone to Agriculture & Allied Sector, Rs. 4348.69 crores to MSE Sector and Rs. 4465.90 crores to Tertiary Sector. It is observed that the targets during the year 2008-09 have substantially been achieved.

#### 4. **ANNUAL CREDIT PLAN 2009-10**

The Annual Credit Plan for the current year 2009-10 envisages a credit lending of Rs. 27439.29 crore in Haryana State out of which Rs. 18859.55 crore (68.7 %) are meant for Agriculture and Allied activities, Rs. 4082.42 crore (14.9%) for SSI Sector and Rs. 4497.32 crore (16.4%) for Tertiary Sector. It is worth mentioning that targets for 2009-10 are higher by 11.5% as compared to those for the year 2008-09.

**ACHIEVEMENTS DURING THE YEAR 2008-2009**  
(April, 2008 to March, 2009)

Parameter	Annual Target (Rs. in crores)	<u>Achievement upto March.09</u>	
		Rs. in Crores	% age
1. Annual Credit Plan			
i) Agr. & allied	17229.67	14201.21	82.4
ii) SSI	3443.59	4348.69	126.3
iii) Tertiary	3935.12	4465.90	113.5
<b>Total</b>	<b>24608.38</b>	<b>23015.80</b>	<b>93.5</b>
	<u>National Goal</u>	<u>Achievement</u>	
	(% age)	(% age)	
2. Credit-Deposit Ratio	60	78	
3. Priority Sector to total credit	40	66	
4. Adv. to Agriculture to total advances	18	35	
5. Adv. to Weaker Sector to total advances	10	12	
6. DRI Advances	1	0.005	

## संस्थागत वित्त एवं साख नियन्त्रण विभाग, हरियाणा

( गतिविधियों व उपलब्धियों पर नोट )

### 1. भूमिका

हरियाणा सरकार संस्थागत वित्त को अधिक महत्त्व देती है क्योंकि वाणिज्य बैंकों, सहाकारी बैंकों व अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गए संस्थागत वित्त से राज्य के बजट स्रोतों पर कम बोझ पड़ता है। हरियाणा में सरकार का कार्य बैंकों द्वारा कृषि व अन्य क्षेत्रों विशेषतया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को महत्व दिलाना रहा है

### 2. हरियाणा में बैंकों का समग्र विस्तार

वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय हरियाणा में केवल 174 बैंक शाखाएं थी जिनकी कुल जमा राशि 64.10 करोड़ रुपये तथा कुल ऋण राशि 30.27 करोड़ रुपये थी और ऋण-जमा अनुपात 47 प्रतिशत था। मार्च 2009 के अन्त में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़कर 2112 हो गयी है जिनकी कुल जमा-राशि 82875 करोड़ रुपये तथा कुल ऋण-राशि 64738 करोड़ रुपये थी अतः ऋण-जमा अनुपात 78 प्रतिशत रहा।

### 3. वार्षिक ऋण योजना 2008-2009 की समीक्षा

वर्ष 2008-2009 के लिए वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत राज्य में 24608.38 करोड़ रुपये के ऋण देने का लक्ष्य था। जिस में से कृषि व सम्बन्धित कार्यों के लिए 17229.67 करोड़ रुपये (70 प्रतिशत) लघु उद्योगों के लिए 3443.59 करोड़ रुपये (14 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र के लिए 3935.12 करोड़ रुपये (16 प्रतिशत) ऋण देने की योजना थी।

वित्त वर्ष 2008-2009 के दौरान मार्च, 2009 के अन्त तक कुल 23015.80 करोड़ रुपये (लक्ष्य का 93.5%) के ऋण प्रदान किए गए । 23015.80 करोड़ रुपये की इस राशि में से 14201.21 करोड़ रुपये कृषि व अन्य क्षेत्रों, 4348.69 करोड़ रुपये लघु उद्योगों व 4465.90 करोड़ रुपये तृतीयक क्षेत्र को दिए गए । उपरोक्तानुसार वर्ष 2008-2009 के लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिए हैं।

#### 4. वार्षिक ऋण योजना 2009-2010

वर्तमान वर्ष 2009-2010 की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में 27439.29 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने का लक्ष्य है । जिसमें से कृषि व अन्य क्षेत्रों को 18859.55 करोड़ रुपये (68.7 प्रतिशत) लघु उद्योगों को 4082.42 करोड़ रुपये (14.9 प्रतिशत) और तृतीयक क्षेत्र को 4497.32 करोड़ रुपये (16.4 प्रतिशत) दिए जाने हैं । यहां यह उल्लेखनीय कि वर्ष 2009-2010 के लक्ष्य वर्ष 2008-2009 की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक हैं ।

वर्ष 2008-2009 के दौरान उपलब्धियां  
( अप्रैल 2008 से मार्च, 2009 तक )

मापदण्ड	वार्षिक लक्ष्य ( करोड़ रुपये )	मार्च, 2009 तक उपलब्धि	
		करोड़ रुपये	प्रतिशत
1. वार्षिक ऋण योजना			
क. कृषि व अन्य	17229.67	14201.21	82.4
ख. लघु उद्योग	3443.59	4348.69	126.3
ग. तृतीयक क्षेत्र	3935.12	4465.90	113.5
<b>कुल</b>	<b>24608.38</b>	<b>23015.80</b>	<b>93.5</b>
		राष्ट्रीय लक्ष्य ( प्रतिशत )	उपलब्धि ( प्रतिशत )
2. ऋण जमा अनुपात ( सकल )		60	78
3. प्राथमिक क्षेत्र को कुल ऋण में से		40	66
4. सीधे कृषि क्षेत्र को कुल ऋण में से		18	35
5. कमजोर वर्ग को कुल ऋण में से		10	12
6. डी.आर.आई. ऋण		1	0.005

\*\*\*